



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 63

नवंबर, 2018

अंक 11

कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

किसानों की सहायता करने की जब बात आती है तो जो व्यक्ति खेती नहीं करता है, वह सोचता है कि किसानों की पहले ही बहुत ज्यादा सहायता की जा रही है और अब किसानों की सहायता करने के लिए फालतू धन नहीं है।



किंतु, जब सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात आती है तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती। लेकिन इसके विपरीत कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि देश की उन्नति के लिए सिस्टम में पैसा फँकना जरूरी है। इस प्रकार से पैसा फँकने का तर्क यह दिया जाता है कि उपभोगताओं की खरीद क्षमता बढ़ेगी। भारत में कई प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जाता है, जैसे की बेकार में कई वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता देकर राज्य के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हालांकि यह आर्थिक सहायता गरीबों के नाम पर दी जाती है, किंतु वास्तव में यह पहले से धनी लोगों को ही मिलती है, अथवा सरकारी राजस्व का दुरुपयोग होता है।

प्रारंभ में हमने सुझाव दिया था कि सातवां वेतन आयोग लागू न किया जाए, इसके बाद हमने यह भी सुझाव दिया कि अगले 10 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए।

सातवें वेतन आयोग से लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए रु. 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यय किया गया है। औसतन यह रु. 1 लाख प्रति कर्मचारी वार्षिक बनता है।

जब हम किसानों की औसत आय से इसकी तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि किसान की आय लगभग रु. 70,000 वार्षिक है अथवा 15 राज्यों में औसत आय केवल रु. 16,000 वार्षिक है, अतः सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इतनी वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए हमारा दृढ़ विचार है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत कटौती की जाए और उस बचत को देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और शिक्षा कार्यक्रमों तथा अन्य उपयोगी सेवाओं में लगाया जाए। प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, अथवा भारत के सभी नागरिकों को विश्व स्तर के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।

किसानों की आय और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अत्यधिक अंतर होने के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन होता है और इसी कारण जातिगत राजनीति, आरक्षण की मांग और समाज में विभाजन की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसी कारण से सरकारी नौकरियों की सबसे अधिक मांग है। हाल ही में एक विज्ञापन में बताया गया है कि देश में 1 लाख रेलवे पदों के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने आवेदन किया। प्रत्येक पद के लिए 280 लोगों ने आवेदन दिया है। यह भी सच है कि उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को कम वेतन मिलता है लेकिन मध्य स्तर और निचे के पदों पर कार्य करने वालों को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। इस प्रकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राजनैतिक दलों के द्वारा अपने-अपने वर्ष 2019 के आम चुनाव के घोषणापत्रों में उठाना चाहिए।

— अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

‘ड्रॉफ्ट पंजाब राज्य किसान नीति’ पर हुए सम्मेलन का सार

डॉ० रमेश चंद, नीति आयोग और 15वें वित्त आयोग के सदस्य

पंजाब राज्य प्रत्येक व्यक्ति के दिल में एक विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है; पंजाबियों के बारे में यह मशहूर है कि वे तंगहाली में भी बहुत कुछ कर सकते हैं; वे आशाएं जगाते हैं और कभी निराश नहीं होते। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि आज पंजाब में क्या हो रहा है, तो उन्हें बहुत निराशा होती है क्योंकि वे पंजाब को अन्य राज्यों से अलग राज्य मानते हैं।

किन्तु यह सच है कि प्रत्येक प्रौद्योगिकी की कुछ समय सीमा होती है और उस निश्चित समय के बाद वह प्रौद्योगिकी व्यर्थ हो जाती है। पंजाब में हरित क्रांति के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी के कारण आज पंजाब की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है।

हरित क्रांति से पंजाब के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अत्यधिक सहायता मिली थी। 1960 के दशक में लोगों के जैसे मकान थे, आज उनके मकान बिल्कुल अलग ढंग के आधुनिक

सुविधाओं से युक्त बने हुए हैं। 1980 के दशक में पंजाब की कृषि में कुछ कमियां देखने में आईं और वर्ष 1985-86 में एक सरकारी समिति ने फसलों के विविधिकरण का मामला उठाया था। पंजाब में कृषि क्षेत्र के उभरते हुए संकट पर मैंने वर्ष 1999 में ईकॉनॉमिक पॉलीटीकल विकली में एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें संभावित विकल्प सुझाए गए थे।

लोग पंजाब में उभरते हुए विरोधाभास के बारे में बात करते हैं; पंजाब में बाहर से लाखों लोग काम करने क्यों आते हैं, जबकि पंजाब का युवा बेरोजगार है। मैंने इसका उत्तर दिया। पंजाब में कई समितियां हैं किन्तु किसी ने कभी कोई कार्यवाही नहीं करी और राजनैतिक नेता चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं।

पंजाब ने बहुत लंबे समय तक कुछ कार्यवाही होने का इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ और अब उम्मीद की जाती है कि पंजाब किसान नीति के कारण कुछ कार्यवाही अवश्य होगी। यदि अब कार्यवाही में विलंब हुआ तो पंजाब की हालत को सुधारना बहुत कठिन हो जाएगा।

मसौदा दस्तावेज के 4 विभिन्न लक्ष्य हैं। पहला, किसानों को जीवनस्तर स्वीकार्य स्थिति तक सुधारा जाए, इसके लिए 2 उपाय हैं। पहला, पंजाब में ही किसान नेताओं और राजनैतिक नेताओं तथा विद्वानों के माध्यम से संभव है। दूसरा, पंजाब से बाहर जो कि बिलकुल अलग है।

पंजाब के बाहर का कोई भी किसान कहेगा कि यदि राज्य में सिंचाई और उच्च पैदावार, निश्चित मॉर्केट और सरकार फसलों की खरीद करती है तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली किसान कौन होगा। पंजाब में यह सब सुविधाएँ हैं, किन्तु वहाँ का किसान इसे अभिशाप समझता है न कि वरदान।

पंजाब के बाहर लोग महसूस करते हैं कि पंजाब के किसान की आय बहुत अधिक है; क्योंकि वहाँ की उत्पादकता और जुताई क्षेत्र के अनुकूल है। राजस्थान में भी जुताई क्षेत्र बहुत है लेकिन उत्पादकता आय बहुत कम है। पंजाब में केवल 0.5 प्रतिशत से कम किसान निर्धन हैं और इसके अतिरिक्त किसान की आय और गैर किसान व्यक्ति की आय में अंतर भी बहुत कम था।

हालांकि पिछले 4 - 5 वर्ष में भी किसान और गैर कृषि से प्राप्त होने वाली आय लगभग बराबर थी। लेकिन इन 4 - 5 वर्ष में कृषि क्षेत्र में विशेष उन्नति न होने के कारण गैर कृषि क्षेत्र की आय किसानों से 30 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।

पंजाब का किसान वहाँ की उपलब्ध विशेष सुविधाओं पर पछता रहा है; उसका मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने और खाद्य सुरक्षा के कारण उन्हें सुनहरे अवसरों से वंचित होना पड़ा है और वे ऋण के बोझ के तले दब चुके हैं। पंजाब में प्रति किसान और प्रति परिवार ऋण

बहुत अधिक है और किसान असंतुष्ट और शोषित महसूस करते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह प्रगति करे। भारत से 4 गुणा अधिक प्रति व्यक्ति आय के देश वाले किसान भी और अधिक कमाना चाहते हैं। इसी प्रकार पंजाब राज्य के किसानों की आय अन्य राज्यों के किसानों से बहुत अधिक होने के बाद भी वे और अधिक कमाना चाहते हैं।

पंजाब के किसानों के जीवनस्तर में कैसे सुधार किया जा सकता है ? यह भी सच है कि जो एक व्यक्ति को स्वीकार्य होगा वह दूसरे को नहीं। विश्व में कई कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी उत्पादकता पंजाब जैसी है लेकिन चीन की उत्पादकता पंजाब से अधिक है; फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में गेहूं की उत्पादकता अधिक है; पंजाब में 1 हेक्टेयर भूमि पर 11 टन धान और गेहूं की फसल उगाई जाती है।

भारत में किसी भी राज्य में ऐसा उत्पादकता वाला क्षेत्र नहीं है। पंजाब के बाहर यदि गेहूं और धान को छोड़कर कुछ फल और सब्जियां उगाता है तो उसकी आय 5 गुणा बढ़ जाएगी। किंतु पंजाब में यह केवल 1:2 के अनुपात में है। पंजाब में उच्च तकनीक की कृषि, विभिन्न मॉडल जैसे विकल्प अपनाने की आवश्यकता है किंतु ऐसा परिवर्तन लाना सरल नहीं है।

यह एक भ्रम है कि यदि बिजली की दरें बढ़ाकर धान की उत्पादकता कम की जा सकती है तो यह सत्य है कि धान का बिजाई क्षेत्र कम नहीं होगा बल्कि पानी का उपयोग कम हो जाएगा। लेकिन धान फसल चक्र से बाहर नहीं हो सकती, इसकी खेती होती रहेगी। इसलिए विभिन्न उपाय, संस्थागत ढांचा और भिन्न नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सके।

संक्षेप में यह है कि पंजाब के किसानों का जीवनस्तर सुधारने के लिए सीमित अवसर हैं, इसलिए पंजाब राज्य में कृषि समस्याओं के समाधान के लिए कृषि से अलग अन्य विकल्पों को ढूंढना ही होगा।

जब पंजाब में कृषि के अंश और कुल मजदूरों में कृषि मजदूरों की बात आती है तो कई विरोधात्मक संकेत सामने आते हैं। प्रति व्यक्ति आय की दर से कोई भी राज्य अथवा देश ऐसा नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था में 35 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का योगदान है।

यदि कोई राज्य या देश पंजाब की प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पहुंचता है तो कृषि में उसका भाग 8 से 10 प्रतिशत ही होगा। यहां कृषि से बहुत आशाएं हैं और इस कारण समस्या का समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है।

मुख्य राष्ट्रीय रुझानों से अलग भिन्नता यह है कि पंजाब की कुल अर्थव्यवस्था के भाग में कृषि का भाग 35 प्रतिशत होने के बावजूद भी यहां के केवल 31 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं।

देश भर के आंकड़ों से यह आंकड़ा अलग है जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 35 प्रतिशत और कृषि में रोजगार का भाग 65 प्रतिशत से अधिक है। इसका विरोधात्मक कारण यह है कि पंजाब में गैर कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। पंजाब का किसान अपनी फसल के लिए अधिक मूल्य पाने के लिए विलाप कर सकता है लेकिन यह समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता।

दूसरा, लक्ष्य है प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए। पंजाब में पर्याप्त मात्रा में जल विद्यमान है और बड़ी मात्रा में मीठा पानी उपलब्ध है। लेकिन एक छिपी हुई समस्या यह है कि कुछ समय के बाद यहां पानी की कमी हो जाएगी। यदि मुफ्त बिजली के बारे में कुछ नहीं किया गया तो यह समस्या गंभीर हो सकती है।

यदि पानी के मूल्यों और उपयोग के लिए कुछ नहीं किया गया तो पंजाब में भी पानी की एक स्थाई समस्या बन जाएगी। धान की पैदावार बंद नहीं होगी लेकिन बिजली के मूल्यों को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि किसान केवल धान के लिए 40 प्रतिशत बिजली का उपयोग करेंगे और पानी की भी बचत होगी, यही मेरे लेख में कहा गया है।

तिसरा लक्ष्य उस छिपी हुई या दिखाई देने वाली समस्या का समाधान करना है — पंजाब में बेरोजगारी की समस्या। पंजाब में दो प्रकार के युवा हैं : एक वह वर्ग जो बिना योग्यता के भी अधिक आय वाली नौकरी चाहते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो योग्य हैं किंतु उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।

ग्रेजुएट युवा भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में कुल कृषि कामगारों में से बाहर से आने वाले कामगारों का अनुपात सबसे अधिक है। पंजाब में कृषि रोजगार के कई अवसर हैं किंतु यहां के लोग नहीं करना चाहते।

इसका समाधान यह है कि कृषि क्षेत्र को इस प्रकार से बनाया जाए की वह युवाओं के हित और सोच के अनुसार लाभकारी बन सके। पंजाब में प्रत्येक किसान परिवार अपने बच्चों को खेती करने की सलाह नहीं देता। यह कभी लाभकारी क्षेत्र था किंतु अब अधिकतम लोग खेती नहीं करना चाहते क्योंकि यह स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती।

पंजाब के युवाओं को मशीनों पर काम करना जैसे ट्रैक्टर चलाना और अन्य मशीनों पर कार्य करना ज्यादा पसंद है। इसके लिए ऐसा समाधान ढूंढना होगा जहां लोगों को मशीनों पर काम करना पड़े ताकि उनके हाथ मैले न हों और उन्हें कौशल पूर्ण कार्य उपलब्ध कराने होंगे जिनसे वे अधिक आय अर्जित कर सकें।

1980 के दशक में मध्य में पंजाब में आतंकवाद के समय कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों में ही तेजी से कमी आई। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद बहुत से राज्यों ने उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाया। उदाहरण के लिए पुणे, बेंगलोर और मैसूर ने सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र खोल लिए जबकि मोहाली जैसे क्षेत्र ने इस अवसर का गंवा दिया। पंजाब राज्य में सेवा क्षेत्रों का भी लाभ नहीं उठाया गया। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पंजाब में कृषि क्षेत्र में कई अवसर हैं किंतु इनका लाभ उठाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उर्वरक और ट्रैक्टरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहां उद्योग लगाने की संभावनाएँ हैं। ऐसा करने पर यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वे कृषि कार्यों से अलग क्षेत्र में काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यह सच है कि खुली अर्थव्यवस्था के दौर में जब तक पंजाब में निवेश करना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा तब तक राज्य से बाहर ट्रैक्टर और उर्वरक तैयार होते रहेंगे। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पंजाब राज्य ने कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य उद्योग क्षेत्रों के अवसर गंवा दिए हैं।

चौथा लक्ष्य उन्नत शासन और डिलिवरी का है जो पंजाब की स्थिति सुधारने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इन सुविधाओं के उपलब्ध न होने से अन्य तीन लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते।

कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार को दोष दे सकता है कि उसकी गलत नीतियों के कारण पंजाब की आज यह स्थिति है। किंतु यह मानना चाहिए कि किसी भी सरकार या नीति निर्माण करने वालों की मंशा किसी राज्य को हानि पहुंचाने की नहीं हो सकती। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर कार्य करने होंगे।

नेताओं को कुछ साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। पानी को छोड़कर, पंजाब में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब की भूमि यूरिया के प्रयोग के कारण खराब हो रही है।

लेकिन मैंने पंजाब में कोई भी खेत ऐसा नहीं देखा जो यूरिया के उपयोग के कारण खराब हुआ हो। पंजाब की भूमि आज भी उतनी ही उपजाऊ है जितनी हरित क्रांति के समय थी, इसे और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कुछ माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स का उपयोग किया जा सकता है। किंतु एक समस्या पानी की अवश्य है उसका भी समाधान प्रौद्योगिकी अपनाकर किया जा सकता है।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0